has occurred. In addition Union Government have suggested short term measures to Delhi to avoid water crisis.

(d) There is no water dispute between Delhi and Haryana at present. Haryana is supplying additional raw water to Delhi on payment from its own share of Ravi -Beas/Yamuna waters keeping in view its own requirement of irrigation and drinking water.

सरकार के समक्ष लम्बित नदी जल विवाद

5199. **श्रीमती स्वराज** : क्या जल संसाधन मंत्री 4 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1766 को दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ये नदी जल विवाद समाधान के लिए कब से लम्बित हैं; और

(ख) क्या सरकार इन विवादों के शीघ्र समाधान के लिए कोई विशेष प्रयास किए जाने के संबंध में विचार कर रही है; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) तमिलनाडु सरकार ने अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत एक अधिकरण गठित करने के लिए जुलाई, 1986 में औपचारिक रूप से अनुरोध किया था। भारत सरकार ने इस बात से स्वयं संतुष्ट होने के बाद कि इस विवाद को बातचीत के जरिए हल नहीं किया जा सकता है, 2 जून, 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण गठित किया था।

पंजाब समझौता पंचाट के पैराग्राफ-9 के अनुसरण में अप्रैल, 1986 में भारत सरकार द्वारा अपनी ओर से रावी व्यास जल अधिकरण गठित किया गया था।

जल संसाधन क्षेत्र में अन्तर्राज्यीय मुद्दों से संबंधित स्थायी समिति को अंबला तक यमुना जल के आबंटन से संबंधित मुद्दा भेजा गया था। समिति की पहली बैठक 11-9-90 को आयोजित की गई थी।

(ख) कावेरी और रावी व व्यास मुद्दे पहले से ही जल विवाद अधिकरणों के पास हैं, यमुना जल के आबंटन से संबंधित मुद्दे का हल इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी भागीदार राज्य एक साथ मिलकर स्थायी समिति की बैठकों में चर्चा करके आम सहमति पर पहुंचते हैं।

Investigation of closure of sluice gates

5200. SHRI CHIMANBHAI MEHTA :
SHRI MOHD. MASUD KHAN :
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY :
SHRI SARADA MOHANTY :
SHRI G. G. SWELL :

Will the Minister of WATE RESOURCES be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Ministry of Environment has decided to send or has already sent a team to SSP to investigate about the closure of sluice gates and its effect on the villagers who are residing in the proposed submerged area ;

(b) if so, whether Government have taken into consideration the Tribunal Award which restricts the review up to 45 years and to be done unanimously by the four concerned States and the Centre ;

(c) what are, the terms of the investigation laid down by Government;

(d) whether the team was sent after consultation with Water Resources Department ;

(e) if not, the reasons therefor ;

(f) the progress of SSP related to construction of dam-height Canal and distributaries till this day ;

(g) what is the amount spent so far on the construction of Dam height, Canal construction, distributaries construction and in acquiring land; and

(h) whether the cement lining of Canal costs one third of the Canal construction .

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to (c) A fact finding team comprising S/Shri S. C. Maudgal (Adviser, Ministry of Environment & Forests), Kushalappa (Regional Chief Conservator of Forests), Bittu Sahgal and Shyam Chainani (Environmentalists), was constituted to visit the project area and report back on the compliance status of environmental action plans, including rehabilitation, in the wake of closure of sluices. The objective of the team is not to review the height of the dam.